



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2013/आश्विन 26, 1935

No. 237]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2013/ASVINA 26, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2013

मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत

विषय : चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) जांच की शुरुआत ।

सं. 15/2/2013—डीजीएडी—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी") कहा गया है, ने 03 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 39/1/99—डी जी ए डी के तहत चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी निश्चित पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. 147/2000—सीमा शुल्क द्वारा आरोपित किया गया।

2. प्रथम निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में इस प्राधिकारी ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचना संख्या 39/1/1999 डी जी ए जी के माध्यम से अपने अंतिम परिणाम को अधिसूचित किया तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए रखने की सिफारिश की। इस प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006—सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया।

3. दूसरी निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 30 जून, 2011 को अधिसूचना संख्या 15/4/2010 डी जी ए जी के माध्यम से अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क निरंतर जारी रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 76/2011—सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया।

4. मैसर्स दीपक नाइट्राइट लि० (जिसे बाद में आवेदक कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (क) के अनुरूप चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने के अनुरोध के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के सतत पाटन तथा उसके फलस्वरूप दूसरी अंतिम निर्णायक जांच के पश्चात पाटनरोधी शुल्क के अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त रूप के आरोपण के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाया है। आवेदक ने वर्तमान बेंचमार्क रूप से नियत रूप तक पाटनरोधी शुल्क के रूप में बदलाव तथा पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में वृद्धि का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

5. पूर्व की जांच तथा वर्तमान एम टी आर आवेदन में विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट एक आक्सीडाइज करने वाला तथा कम करने वाला एजेंट है। यह एक सफेद क्रिस्टल जैसा पाउडर है जिसका अधिकांशतः उपयोग पैरासीटामोल, एनलजीन, थियोफिलीन, कैफीन के उत्पादन के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योगों, रंग उद्योगों, ल्यूब्रीकेन्ट्स, निर्माण संबंधी रासायनिक पदार्थ, रबड़ सुखाने वाले एजेंट, ताप अंतरण, नमक, मांस की प्रोसेसिंग, वस्त्र आदि में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि पूर्व की जांच में दर्शाया गया है। सोडियम नाइट्राइट का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 28341010 के अंतर्गत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है अथवा विचाराधीन जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समीक्षा का आधार

6. एम टी आर के लिए वर्तमान आवेदन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

क. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित मूल्य पर अत्यधिक मात्रा में आयात हो रहा है।

ख. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त है जिससे सतत पाटन तथा फलस्वरूप क्षति हो रही है।

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा एवं स्वरूप पाटन का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है तथा अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की जाए तथा इसके स्वरूप को बेंचमार्क से बदलकर नियत स्वरूप किया जाए।

शुरूआत:

8. नियम 23 (1 क) में मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। 1 मार्च, 2011 को सी.शु. अधिसूचना सं० 15/2011 के तहत यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 निम्नानुसार है :

(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

9. प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करना प्रथमदृष्टया उचित समझते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

प्रक्रिया

11. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना जिससे लागू उपाय की समीक्षा करना आवश्यक हो, के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह विचार करते हैं कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/4/2010-डी जी ए जी के माध्यम से अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना 76/2011-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाई गई निश्चित शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा शुरू करना उपयुक्त है। प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के प्रावधानों के अनुरूप जांच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में दिनांक 30 जून, 2011 के पूर्व की अधिसूचना संख्या 15/4/2010-डी जी ए डी तथा केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना 76/2011-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाई गई निश्चित शुल्कों के सभी पहलू शामिल होंगे।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

12. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा पी ओ आई (2012-13) शामिल होगी। प्राधिकारी संभावित विश्लेषण के लिए पी ओ आई पश्चात अवधि के संबंध में आंकड़ों की भी जांच कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा इस जांच की शुरु होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा अन्य प्रकार की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना देने तथा प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तर दायर करने तथा अपनी टिप्पणियां देने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए ।

18. किसी चित्रांकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । गोपनीय रूपांतरण की पांच (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की पांच (5) प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

19. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2013

Initiation of Mid-term Review Investigation

Subject: Initiation of Mid-term Review (MTR) investigation in respect of the anti-dumping duties imposed on the imports of Sodium Nitrite, originating in or exported from China PR.

No. 15/2/2013-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified its final findings vide Notification No. 39/1/99-DGAD dated 3rd November, 2000 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the

subject country). The definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No.147/2000-Customs dated 19th December, 2000.

2. Pursuant to the first sunset review, the Authority notified its final findings vide Notification No. 39/1/1999-DGAD dated 1st December, 2005 and recommended continued imposition of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 3/2006—Customs dated 17th January, 2006.

3. Pursuant to the second sunset review, the Authority notified its final findings vide Notification No. 15/4/2010 - DGAD dated 30th June, 2011 and recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 76/2011-Customs dated 17th August, 2011.

4. M/s Deepak Nitrite Limited (hereinafter referred to as the applicant) has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duty imposed on the imports of Sodium Nitrite, originating in or exported from China PR, in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The applicant has alleged continued dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry, due to imposition of inadequate and inappropriate form of anti-dumping duty, post 2nd sunset review investigation. The applicant has requested for change in the form of anti-dumping duty from current benchmark form to fixed form and enhancement in the quantum of anti-dumping duties.

Product under Consideration:

5. The product under consideration in the earlier investigation's as well as the present MTR application is Sodium Nitrite. Sodium Nitrite is an oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in Pharmaceuticals industries for production of Paracetamol, Analgin, Theophylline, Caffeine, Dye industries, Lubricants, Construction chemicals, Rubber blowing agent, Heat transfer salts, meat processing, Textiles, etc. The product under consideration remains the same as in the earlier investigations. Sodium Nitrite is classified under heading 28341010 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

Grounds for Review:

6. The present application for MTR has been made on the following grounds:

- a. Significant volume of imports taking place at dumped prices inspite of anti-dumping duty being in force.
- b. Inadequate and inappropriate existing anti-dumping duty causing continued dumping and consequent injury.

7. The Applicant has submitted that the existing quantum and form of the anti-dumping duty is insufficient to counteract dumping and requested for enhancement of the anti-dumping duty and change in its form from bench mark to fixed form.

Initiation:

8. Rule 23 (1A) lays down the scope of a Mid-Term Review. Rule 23 of the AD Rules as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March, 2011 reads as follows:

“(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

9. On the basis of information made available by the aforementioned applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Country involved:

10. The country involved in the present investigation is China PR.

Procedure:

11. Having regard to the information provided by the Applicant necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No. 15/4/2010-DGAD dated 30th June, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification 76/2011-Customs dated 17th August, 2011. The Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules. The review will cover all aspects of the earlier Notification No. 15/4/2010-DGAD dated 30th June, 2011 and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification 76/2011-Customs dated 17th August, 2011.

Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2012 to 31st March, 2013. The injury investigation period will however cover the periods 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI (2012-13). The authority may also examine the data pertaining to the post-POI period for likelihood analysis.

Submission of Information:

13. The exporters in subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110011.**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the

information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J.S. DEEPAK, Designated Authority